बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-246
09/05/2020

मुख्यमंत्री ने की कोविड–19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी एवं रोकथाम के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की उच्चस्तरीय समीक्षा, मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश

- स्किल सर्वे के आधार पर रोजगार सृजन की कार्रवाई की जाय, आवश्यकतानुसार इनसे संबंधित निर्माण इकाईयों की स्थापना राज्य में ही करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाय ताकि यहीं पर उन्हें स्थायी रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके

- जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा में भी आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करायी जाय ताकि आसपास के जिले के लोगों को सुविधा हो

- सभी जिलों में आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ायी जाय

- डॉक्टर, नर्सेज एवं अन्य पारा मेडिकल स्टाफ जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये दिन–रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाय, उनके लिये पी0पी0ई0 किट्स, मास्क इत्यादि की पर्याप्त उपलब्धता हो

- मुख्यमंत्री का सुझाव– पंचम वित्त आयोग की राशि से ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिये साबुन, सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध कराया जा सकता है

- ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में दरी, बिछावन, मच्छरदानी, मॉस्किटो क्वायल की समुचित व्यवस्था हो ताकि लोगों को परेशानी न हो। महिलाओं एवं बच्चों के लिये अलग व्यवस्था रखी जाय ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हुये सर्वेक्षण के आधार पर जल्द से जल्द नये राशन कार्ड लोगों को उपलब्ध करायें। अगर इस कार्य में कोई पदाधिकारी शिथिलता बरतते हैं तो उन्हें चिन्हित कर समुचित कार्रवाई की जाय

- मुख्य सचिव को निर्देश कि बाहर से पैदल चलकर आने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुॅचाने की करें व्यवस्था। लोगों से अनुरोध कि बाहर से पैदल चलकर न आयें। निकटतम प्रखण्ड/थाने में पहुॅचकर सूचना दें

पटना, 09 मई 2020 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कोविड–19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी एवं रोकथाम के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से उच्चस्तरीय समीक्षा की।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि अब तक राज्य में 589 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें 318 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये 5 लोग किसी और गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित थे। 96 कोरोना पॉजिटिव मरीज राज्य में बाहर से आये लोग हैं। उन्होंने बताया कि बाहर से आये रेड जोन के लोगों का रैंडम सैंपलिंग कराया जा रहा है। दवाओं, उपकरणों इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों में 72 हजार लोग आवासित हैं और वहॉ सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी गयी हैं। सभी के फोन नंबर उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और उसके आधार पर कार्य किया जा रहा है।

प्रधान सचिव ग्रामीण विकास श्री अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब तक 8 लाख 43 हजार मस्टर रोल सृजित किये गये हैं। मनरेगा के माध्यम से आहर, पईन का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। जल–जीवन–हरियाली के माध्यम से भी रोजगार सृजित किये गये हैं।

ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री विनय कुमार ने बताया कि 20 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। ढ़ाई हजार कार्य शुरू किये गये हैं, जिसके माध्यम से प्रतिदिन 18 से 20 हजार लोगों को रोजगार दिये जा रहे हैं। टोला सम्पर्क योजना के बचे काम को जल्द पूरा किया जा रहा है।

जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजीव हंस ने बताया कि 15 मई तक 382 में से 110 योजनायें पूर्ण हो जायेंगी और 30 मई तक कुल 350 योजनायें पूर्ण हो जायेंगी। इसके माध्यम से 12 से 15 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है।

प्रधान सचिव पंचायती राज श्री अमृत लाल मीणा एवं सचिव खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री पंकज कुमार पाल ने भी किये जा रहे कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।

समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल सर्वे के आधार पर प्रवासी श्रमिकों के लिये रोजगार सृजन की कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार इनसे संबंधित निर्माण इकाईयों की स्थापना राज्य में ही करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाय ताकि यहीं पर उनके स्किल के अनुसार उन्हें स्थायी रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा में भी आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करायी जाय ताकि आसपास के जिले के लोगों को सुविधा हो। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ायी जाय। डॉक्टर, नर्सेज एवं अन्य पारा मेडिकल स्टाफ जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये दिन–रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाय तथा उनके लिये पी0पी0ई0 किट्स, मास्क इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिये भी हम सबको विशेष ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पंचम वित्त आयोग की राशि से ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिये साबुन, सैनिटाइजर तथा जीविका द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों पर समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था रहे। आपदा प्रबंधन विभाग के एस0ओ0पी0 के अनुसार सारी व्यवस्थायें सुनिश्चित हों। उन्होंने कहा कि ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में दरी, बिछावन, मच्छरदानी, मॉस्किटो क्वायल की समुचित व्यवस्था हो ताकि लोगों को परेशानी न हो। महिलाओं एवं बच्चों के लिये अलग व्यवस्था रखी जाय ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हुये सर्वेक्षण के आधार पर जल्द से जल्द नये राशन कार्ड लोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर अगर इस कार्य में कोई पदाधिकारी शिथिलता बरतते हैं तो उन्हें चिन्हित कर समुचित कार्रवाई की जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से पैदल चलकर आने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुॅचाने की व्यवस्थायें होनी चाहिये। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाहर से पैदल चलकर न आयें। निकटतम प्रखण्ड/थाने में पहुॅचकर सूचना दें ताकि उन्हें उनके गंतव्य तक पहुॅचाया जा सके।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, पथ निर्माण, पंचायती राज एवं लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री संजय कुमार, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास श्री अरविंद कुमार चौधरी, सचिव खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री पंकज कुमार पाल, सचिव जल संसाधन श्री संजीव कुमार हंस सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव जुड़े थे।

******